(ख) और (ग) ग्रामीण बस्तियों में पेयजल की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण के भाग–1 के आंकडे अभी तक 23 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो चुके हैं । पेयजल की गुणवत्ता के बारे में सर्वेक्षण के भाग–2 से संबंधित आंकड़े 6 राज्यों से प्राप्त हुए हैं । आंकडों का विश्लेषण करते समय बड़े पैमाने पर अनियमिततायें पाई गई थीं । सभी राज्य सरकारों से आंकड़ों की पुन: पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से सही किए गए आकड़ें अभी प्राप्त होने हैं । यह भी निर्णय लिया गया है कि बिना जल स्रोत वाली मुख्य बस्तियों और 30% अन्य बस्तियों की पूरी जांच भी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा ही कराई जाए ।

जवाह रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को आवंटित राशि

3239. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई तथा जारी की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दी गई राशि आवश्यकता से कम थी जिसके कारण सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव बड़ा है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) (क) और (ख) 1991 92 और 1992–93 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के सूखा प्रभावित जिलों सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को आवंटित और रिलीज की गई केंद्रीय निधियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं, (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) जी नहीं । देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधियां आवंटित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त 1993–94 के दौरान देश के 120 चयन किए गए पिछडे जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना के अतिरिक्त निधियां आवंटित की गई हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के 12 जिले शामिल हैं जहां बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की बहुतायत है । गहन जवाहर रोजगार योजना के लिए चहन किए गए पिछडे जिलों की सूची में उन जिलों को शामिल किया गया है जिनके अधिकांश खण्ड सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम द्वारा कवर होते हैं ।

उत्तर प्रदेश को सुनिश्चित रोजगार योजना जिसे 2 अक्टूबर, 1993 से देश के सभी पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली खन्डों में आरंभ किया गया है । जिनमें उत्तर प्रदेश के 145 खंड शामिल हैं, के अंतर्गत भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ये खंड देश के दूर-दराज और पिछडे क्षेत्रों में स्थित हैं और समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कवर होते हैं ।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1991–92 तथा 1992–93 के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित निधियों एवं रिलीज की गयी निधियों के जिलावार ब्यौरे

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	जिला का नाम	1991–92 के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित निधियां	1991–92 के दौरान केन्द्र द्वारा रिलीज की गई निधियां	1992–93 के दौरान केन्द्र द्वारा आबंटित निधियां	1992–93 के दौरान केन्द्र द्वारा रिलीज की गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर काशी	204.81	946.54	215.37	225.58
2.	चमोली	209.62	225.16	225.68	269.28
3.	टेहरी गढवाल	271.95	594.68	274.03	335.40
4.	देहरादून	254.79	241.71	268.47	308.76
5.	गढवाल	368.90	358.19	337.96	328.06
6.	पिथोरागढ	284.10	257.45	295.03	325.33
7.	अल्मोड़ा	454.34	416.99	440.96	482.06
8.	नैनीताल	622.83	558.07	513.39	547.38
9.	सहारनपुर	622.74	448.27	713.01	838.28
10.	मुजफ्फरनगर	570.73	569.84	650.12	791.43
11.	बिजनौर	953.85	871.10	733.22	727.20
12.	मेरठ	607.82	516.21	751.97	878.94
13.	गाजियाबाद	455.12	408.46	437.79	529.91
14.	बुलन्दशहर	787.96	694.06	732.46	900.29
15.	मुरादाबाद	823.06	722.11	699.17	744.89
16.	रामपुर	259.86	223.70	238.64	338.49
17.	बदायूं	519.73	458.18	548.88	677.69
18.	बरेली	552.82	488.02	423.74	504.27
19.	पीलीभीत	308.86	308.86	300.76	346.59
20.	शाहजहांपुर	480.58	431.36	441.88	549.34
21.	अलीगढ	766.07	632.89	807.49	969.15
22.	मथुरा	651.44	629.84	561.44	412.22
23.	आगरा	595.04	512.52	528.19	600.36

1	2	3	4	5	6
24.	एटा	464.60	379.24	534.12	752.92
25.	मैनपुरी	350.08	289.51	435.58	516.75
26.	फरुखाबाद	565.54	449.12	554.54	665.03
27.	इटावा	697.66	504.66	584.40	580.16
28.	कानपुर देहात	870.33	801.55	817.96	923.23
29.	फतेहपुर	603.86	447.91	576.86	693.16
30.	इलाहाबाद	1600.89	1335.51	1569.16	2080.90
31.	झांसी	518.53	486.03	556.88	705.20
32.	झांसी	612.49	546.11	633.49	856.71
33.	ललीतपुर	277.56	277.56	272.69	470.35
34.	हमीरपुर	701.24	593.98	701.46	742.75
35.	बांदा	744.12	509.54	865.94	1122.60
36.	खेरी	791.91	734.61	816.98	903.95
37.	सीतापुर	968.56	490.38	1070.19	1740.83
38.	हरदोई	890.37	565.18	949.16	1462.48
39.	उन्नाव	896.02	777.50	781.49	818.14
40.	लखनऊ	498.03	380 47	506.74	626.50
41.	राय बरेली	985.46	985.46	782.72	880.98
42.	बहराइच	787.92	687.38	726.96	825.59
43.	गोंडा	933.46	918.88	873.76	1035.85
44	बाराबांकी	748.10	696.62	684.33	874.16
45.	फैजाबाद	837.20	490.09	847.79	986.98
46.	सुल्तानपुर	1025.93	818.86	840.81	969.55
47.	प्रतापगढ	649.53	540.22	693.58	948.20
48.	बस्ती	882.55	769.71	831.80	782.03
49.	गोरखपुर	861.00	491.86	1144.36	1326.33
50.	देवरीया	1197.61	1042.10	939.08	649.77
51.	आजमगढ़	967.13	726.94	1053.88	1251.59
52.	जौनपुर	818.24	629.67	891.68	1284.84
53.	बलिया	605.64	528.81	620.58	747.39
54.	गाजीपुर	750.40	669.89	734.84	873.16
55.	वाराणसी	1288.82	1165.34	1068.42	1230.31
56.	मिर्जापुर	794.07	709.66	779.41	813.44

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57.	सोनभद्र . .	654.02	654.02	597.77	603.02
58.	मऊनाथभंजन . .	491.84	284.87	380.33	393.58
59.	सिद्धार्थनगर . .	495.85	456.24	570.17	668.15
60.	हरिद्वार . .	305.10	295.08	277.09	342.87
61.	फिरोजाबाद . .	343.84	306.87	386.14	461.39
62.	कानपुर नगर . .	189.82	166.79	192.66	218.77
63.	महाराजगंज . .	582.35	464.38	580.44	649.53
	योग : . .	40874.69	35637.61	39865.89	47110.04

गुजरात में पेयजल परियोजनाएं

3240. श्री राम सिंह राठवा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में गुजरात में पेयजल परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने और उन्हें क्रियान्वित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा के क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा राज्य के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कुछ परियोजनाओं को शुरू किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां । तथापि मिनी मिशन परियोजनाओं के मामले में राज्य सरकार और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा योजनायें/परियोजनायें कार्यान्वित की जाती हैं ।

(ख) 1993–94 के लिए त्वरित ामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत 6.56 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से अभी तक 21.13 करोड रुपए रिलीज किए जा चुके हैं । शेष राशि 31–3–94 तक रिलीज कर दिए जाने की संभावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) पेयजल में अधिक फ्लोराइड की समस्या को दूर करने के लिए गुजरात के अनेक जिले के लिए 16.24 करोड रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं । इनमें 5.322 करोड रुपए की अनुमानित लागत वाली 3 योजनायें अहमदाबाद, भावनगर और पंचमहल के सूखा प्रभावित जिलों के 98 गांवों के लाभ के लिए हैं ।

Inclusion of land reform laws in the Ninth Schedule

3241. SHRI SOM PAL:
SHRI IQBAL SINGH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have taken a decision to include the land reform laws in the Ninth Schedule of the Constitution; if so, the details thereof and the reasons therefor;

(b) whether Government propose to relax the land ceiling limit for companies to attach investment in export-oriented products;